शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक – 42 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 23 – 30 अक्तूबर 2023 मूल्य पांच रूपये

कांग्रेस की गारंटियों पर भाजपा हुई आक्रामक

- सुक्खू का व्यवस्था परिवर्तन हाईकमान के गले की फांस बना
- डॉ. संबित पात्रा की वार्ता के बाद गारंटीयां बनी मुद्दा
- जय राम, बिन्दल और अनुराग सभी हुए हमलावर

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन और विधानसभा चुनाव में जारी की गयी गारंटीयों पर अब तक अमल न हो पाना अब हाईकमान के लिए भी राष्ट्रीय स्तर पर गले की फांस बनता जा रहा है। यह सवाल इसलिये प्रासंगिक हो गया है कि जिन पांच राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं उन राज्यों में भी कांग्रेस मतदाताओं से इसी तर्ज पर कुछ वायदे करने जा रही है। भाजपा कांग्रेस के वादों पर हिमाचल का उदाहरण देते हुए यह सवाल कर रही है कि जब हिमाचल में ही किये हुये वादों पर अमल करने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया जा सका है तो ऐसे में इन राज्यों में किये जा रहे वादों पर कैसे विश्वास किया जा सकता है। हिमाचल से ही ताल्लुक रखने वाले भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा और सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर इन गारंटीयों के नाम पर काफी आक्रामक हुये पड़े हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में गारंटीयों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिन्दल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने जब प्रदेश में इन गारंटीयों को लेकर सुक्खू सरकार को घेरना शुरू किया तो इसका संज्ञान लेते हुये भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा ने भी प्रदेश का रुख कर लिया। डॉ. पात्रा ने सारी स्थिति का अध्ययन करके शिमला में एक पत्रकारवार्ता करके प्रदेश सरकार से गारंटीयों पर कड़े सवाल पूछ लिये। डॉ. पात्रा ने इन गारंटीयों को लेकर कांग्रेस की राष्ट्रीय महामंत्री प्रियंका गांधी को भी घेर दिया। क्योंकि कुछ गारंटीयों के वायदे उनसे भी करवा दिये गये थे। लेकिन डॉ. पात्रा के सवालों का जवाब प्रदेश सरकार और संगठन की ओर से कोई नहीं दे पाया। क्योंकि जमीनी

सच्चाई यही है की गारंटीयों पर अमल की दृष्टि से कोई काम हुआ ही नहीं है।

बल्कि जिस व्यवस्था परिवर्तन को एक बड़े नारे के रूप में उछाला गया था आज कांग्रेस के मंत्री और दूसरे नेता इस

व्यवस्था परिवर्तन को परिभाषित करने से भी डर रहे हैं। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर यह व्यवस्था परिवर्तन पिछली भाजपा सरकार द्वारा चलाई गई व्यवस्था को ही ढोये रखने का पर्याय बन कर रह गया है। आज आम सवाल पूछा जा रहा है कि जिन अधिकारियों को लेकर कांग्रेस बतौर विपक्ष कड़े सवाल सदन में उठा चुकी है वही अधिकारी इस सरकार के भी अति विश्वस्तों की सूची में पहले स्थान पर हैं। सत्ता परिवर्तन होते हीबड़े स्तर

पर पहले दस दिन में ही प्रशासनिक फेरबदल हो जाता था और जनता में भी सत्ता परिवर्तन का सन्देश चला जाता था। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर इस सरकार ने शिमला के जिलाधीश तक को नहीं बदला। इसी व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर यह सरकार कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों के दौरान जारी किये गये आरोप पत्र को आज तक विजिलैन्स को जांच

के लिये नहीं भेज पायी है। भ्रष्टाचार को संरक्षण देना शायद इस सरकार की नीयत और नीति दोनों बन गयी है। जिस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष राजेंद्र राणा को विधानसभा में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के

भ्रष्टाचार को लेकर पूछे गये अपने ही सवाल को अन्तिम क्षणों में वापस लेना पड़ा हो वहां भ्रष्टाचार की क्या स्थिति होगी और भ्रष्टाचारी कितने पावरफुल होंगे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है।

आज हिमाचल सरकार कांग्रेस की कार्यपद्धति और उसके चुनावी वायदों की व्यवहारिकता का ऐसा प्रमाण पत्र राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप ही खड़ा हो गया जिसका कोई जवाब किसी नेता के पास नहीं रह गया है। इस समय कांग्रेस का कोई भी छोटा बड़ा नेता भाजपा के खिलाफ एक शब्द भी बोल पाने की स्थिति में नहीं रहा गया है। जिन सवालों पर यही कांग्रेस भाजपा को सदन में घेरती थी आज एक भी सवाल पूछने का सहास नही कर पा रही है। आज राष्ट्रीय स्तर पर मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने से विपक्षी राजनीति के समीकरणों में जो बदलाव आया उसके परिदृश्य में कांग्रेस को अपनी राज्य सरकारों पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है क्योंकि इन्हीं सरकारों की कारगुजारी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के लिए गुण दोष सिद्ध होंगी। क्योंकि भाजपा ने सुक्खू सरकार की कथनी और करनी को ऐसे समय राष्ट्रीय प्रश्न बना दिया है जब मुख्यमंत्री स्वस्थ्य कारणों से एम्स में दाखिल है और भाजपा के किसी भी सवाल का सीधे जवाब देने की स्थिति में नहीं है। पांच राज्यों का चुनाव जीतने के लिये भाजपा जिस तरह की गेम प्ले करने पर आ गयी है उसके परिदृश्य में हिमाचल में भी भाजपा द्वारा ऑपरेशन कमल की विसात बिछाने को नजरअन्दाज करना आसान नहीं होगा। क्योंकि मुख्य संसदीय सचिवों का मामला प्रदेश उच्च न्यायालय में चल ही रहा है।

राज्यपाल ने 'मेरी माटी मेरा देश' कार्यक्रम की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन में 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र तथा भारतीय तिब्बत सीमा बल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता की।

इस अवसर पर उन्होंने नेहरू युवा केंद्र के स्वयसेवकों तथा आई.टी.बी.पी. के जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि जननी व जन्मभूमि की महता स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारत शूरवीरों की धरती है, जहां के हर प्रांत में स्वतंत्रता सेनानी व सेना के जवान हैं, जिन्होंने देश के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर कार्यान्वित किए गए इस कार्यक्रम से व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित हुई है। प्रधानमंत्री की दूरदर्शी सोच व देश प्रेम की भावना से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए राज्यपाल ने कहा कि यह कार्यक्रम नई युवा पीढ़ी में देश भक्ति व देश सेवा की भावना को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत आरम्भ किया गया है।

राज्यपाल ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 'मेरी माटी मेरा देश' अभियान गांवों व कस्बों के गुमनाम नायकों व शूरवीरों की स्मृतियों को संजोए रखने के लिए शुरू किया है। इस अभियान से स्वतंत्रता संग्राम में जान न्यौछावर करने वाले ऐसे अनेक शहीदों का योगदान सामने आया है जिनका नाम उनके गांव वालों ने भी भूला दिया था। देश भर में शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर सम्बन्धित गांव में शहीदों के नाम शिलाफलकम पर लिखे गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत युवा स्वयंसेवकों ने अपने गांव और शहीदों के घर से एक चुटकी मिटी व पौधे एकत्रित किए हैं। देश भर से मिटी के 7500 कलशों में लाई गई मिटी से दिल्ली में अमृत वाटिका का निर्माण होगा। पौधों को शहीद वाटिका में लगाया जाएगा ताकि आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा में शहीदों के बलिदान से अवगत करवाया जा सके।

शुक्ल ने कहा कि देशहित सर्वोपरि है। समाज के प्रत्येक वर्ग का कर्त्तव्य है कि वह देश की रक्षा में तैनात सैनिकों का सम्मान करे। उन्होंने बर्फीले व कठिन क्षेत्रों में देश की सीमा पर तैनात आई.टी.बी.पी. के जवानों द्वारा दी जा रही सेवाओं के लिए उनका आभार प्रकट किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने प्रदेश के सभी गांवों, शहरी निकायों तथा आई.टी.बी.पी. के जवानों द्वारा प्रदेश के विभिन्न 10 दर्रो से एकत्रित मिटी के कलशों को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया।

उन्होंने दिल्ली जाने वाले नेहरू युवा केंद्र के स्वयंसेवकों को दिल्ली रवाना करते हुए कहा कि वे हिमाचल प्रदेश के गौरव को बनाये रखने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वे याद रखें कि उनका सम्बन्ध ऐसे प्रदेश से है जिसे मेजर सोमनाथ की शहादत पर देश के पहले परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था।

राज्यपाल ने उपस्थित जनसमूह को भारत को विकसित देश बनाने में अपनी सहभागिता दर्ज करवाने की शपथ भी दिलवाई।

निदेशक नेहरू युवा केंद्र ईरा प्रभात ने राज्यपाल का स्वागत किया तथा प्रदेश में नेहरू युवा केंद्र की उपलब्धियों का विस्तृत ब्योरा दिया। कमाडैंट केंद्रीय सीमा सुरक्षा बल केदार रावत ने राज्यपाल को स्मृति चिन्ह भेंट किया।

राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य को शपथ दिलाई

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राजभवन में आयोजित गरिमापूर्ण समारोह में डा. अंजू शर्मा को हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।

इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी उपस्थित थीं।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया, राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, विधायक केवल सिंह पठानिया और मलेंद्र राजन, हिमाचल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष रामेश्वर सिंह ठाकुर, लोकायुक्त न्यायमूर्ति चंद्र भूषण बारोवालिया, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, हिमाचल लोक सेवा आयोग की सदस्य डा. रचना गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, सचिव बागवानी राकेश कंवर, निदेशक पर्यटन अमित कश्यप, हिमाचल लोक सेवा आयोग के सचिव डी.के. रतन, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा ने कार्यवाही का संचालन किया।

राज्यपाल ने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने अटल टनल रोहतांग का दौरा किया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने सामरिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण इस सुरंग के निर्माण को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार और विशेषतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह टनल जनजातीय क्षेत्र के लोगों के विकास तथा पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण साबित हो रही है। भारी बर्फबारी के दौरान यातायात सुचारू बनाए रखने में भी यह सुरंग कारगर सिद्ध हो रही है।इस अवसर पर सीमा सड़क संगठन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

इसके उपरांत, राज्यपाल ने लाहौल-स्पीति जिला के विख्यात त्रिलोकीनाथ मंदिर में पूजा-अर्चना की तथा प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि की कामना की।

राज्यपाल ने किया अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारम्भ

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कुल्लू के रथ मैदान में सप्ताह भर चलने वाले अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरे का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने भगवान रघुनाथ जी की रथयात्रा में भी भाग लिया। इस अवसर पर लेडी गवर्नर जानकी शुक्ला भी उपस्थित थीं।

राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह पर्व सत्य की असत्य पर जीत का परिचायक है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की संस्कृति बहुत समृद्ध व अद्वितीय है, जिसकी विश्व भर में अलग पहचान है। प्रदेश में वर्ष भर आयोजित होने वाले मेले और त्यौहार यहां के लोगों की समृद्ध परम्पराओं और धार्मिक आस्था को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि आज के समय में प्रदेश के लोगों ने यहां की समृद्ध संस्कृति, रीति-रिवाज़ तथा परम्पराओं को संजोकर रखा है, जिसके लिए यहां के लोग प्रशंसा के पात्र हैं।

राज्यपाल ने कहा कि देवभूमि की पवित्रता नशे के कारण धूमिल हो रही है। नशा घर-घर तक पहुंच रहा है। देवभूमि हिमाचल में नशे का कोई स्थान नहीं है। प्रदेश की समृद्ध संस्कृति

को संजोए रखने के लिए हमें नशे के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, जिसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना होगा। इसके उपरांत, राज्यपाल ने विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड, निगमों व अन्य गैर-सरकारी संस्थानों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया और स्टालों पर जाकर विभिन्न उत्पादों का अवलोकन किया। इस उत्सव में जिला कुल्लू के विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 300 देवी-देवता भाग ले रहे है।

इससे पहले, राज्यपाल ने कुल्लू के प्रसिद्ध लाल चंद प्रार्थी कला केंद्र में अंतरराष्ट्रीय लोकनृत्य उत्सव कुल्लू दशहरा-2023 का शुभारंभ भी किया। इससे पहले, राज्यपाल का भुंतर हवाई अड्डे पर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश संजय करोल, मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, सांसद प्रतिभा सिंह, विधायक रवि ठाकुर, भुवनेश्वर गौड़, सुरेंद्र शौरी, अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

करवा चौथ पर पर्यटन निगम नि:शुल्क उपलब्ध करवाएगा सरगी व पूजा की थाली

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के निदेशक अमित कश्यप ने यहां बताया कि पहली नवम्बर को करवा चौथ त्यौहार के शुभ अवसर पर निगम द्वारा विशेष पैकेज जारी किया गया है।

उन्होंने कहा कि इस दौरान 31 अक्तूबर और पहली नवम्बर, 2023 को पर्यटन निगम के किसी भी होटल में ठहरने पर विवाहित दम्पत्ति को कमरे के किराए में दस प्रतिशत अतिरिक्त डिस्काउंट प्रदान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा सरगी का भी प्रबन्ध किया जाएगा और उन्हें फेणी, केला, दूध, गुलाब जामुन और मठड़ी इत्यादि नि:शुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही अर्घ, पूजा की थाली और करवा जिसमें चावल, उड़द दाल, दूर्बा, पुष्प और कुमकुम इत्यादि भी पर्यटन निगम द्वारा नि:शुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। करवा चौथ पर इन मेहमानों को विशेष व्रत थाली भी परोसी जाएगी। इसके अतिरिक्त करवा चौथ पूजा में आवश्यक सूखा मेवा, पुना, सुहागी जिसमें बिन्दी, चूड़ी, काजल, रिब्बन, मेंहदी इत्यादि का प्रबन्ध भी पर्यटन निगम द्वारा निर्धारित दरों के आधार पर किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक ने कहा कि करवा चौथ का त्यौहार देश के विभिन्न भागों में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। यह त्यौहार पति-पत्नी के मध्य एक पवित्र बंधन का प्रतीक है और विवाहित जोड़े हिमाचल प्रदेश पर्यटन निगम के होटलों में ठहर कर इस पवित्र त्यौहार को और भी अविस्मरणीय बना सकते हैं। इसके लिए वह आकर्षक डिस्काउंट पैकेज का भी लाभ उठा सकते हैं।

शरद नवरात्रों के दौरान प्रदेश के शक्तिपीठों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़

शिमला/शैल। 15 से 23 अक्तूबर 2023 तक प्रदेश के शक्तिपीठों में शरद नवरात्रों के मेलों के दौरान विभिन्न शक्तिपीठों में प्रदेश व पंजाब, हरियाणा, दिल्ली समेत अन्य राज्यों से आये 12 लाख 72 हजार 042 श्रद्धालुओं ने अपना शीश नवाया। मेलों के दौरान सबसे ज्यादा श्रीनयना देवी में 03 लाख से ज्यादा व माता बाला सुन्दरी में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने श्रद्धा पूर्वक अपना शीश नवाया व 96 हजार से ज्यादा वाहनों को आवागमन हुआ।

हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा इन शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की सुरक्षा, कानून एवं व्यवस्था तथा यातायात व्यवस्था को सुनिशिचित करने के लिए ठोस प्रबन्ध किए थे। मेलों के दौरान कोई भी सड़क दुर्घटना, अन्य दुर्घटना व श्रद्धालुओं की कोई भी जान-माल की हानि नहीं हुई।

संजय कुन्डू, पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को शरद नवरात्रों के सफलता पूर्वक आयोजन पर हार्दिक बधाई दी है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक: जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के आपदा प्रभावित 1162 परिवारों को वितरित की 8.97 करोड़ रुपये की मुआवज़ा राशि

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुनर्वास योजना के तहत भारी बारिश एवं भूस्खलन से आई आपदा से प्रभावित जिला बिलासपुर के 1162 परिवारों को 8.97 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि वितरित की। उन्होंने जिला बिलासपुर में आपदा के दौरान जिन 94 प्रभावित परिवारों के घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें पहली किश्त के रूप में 3-3 लाख रुपये प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने बिलासपुर

सदर विकास खंड के अंतर्गत 404 परिवारों को 3.93 करोड़, घुमारवीं विकास खंड के अंतर्गत 532 आपदा प्रभावित परिवारों को 4.55 करोड़ रुपये, झंडूता विकास खंड के तहत 198 आपदा प्रभावित परिवारों को 1.21 करोड़ रुपये तथा स्वारघाट विकास खंड के अंतर्गत 28 आपदा प्रभावित परिवारों को 19.10 लाख रुपये जारी किए।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विशेष राहत पैकेज को लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले, लेकिन अब तक कोई विशेष राहत पैकेज नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 12000 करोड़ रुपये के दावे केंद्र सरकार को भेजे हैं। उन्होंने केन्द्र से आग्रह किया कि वे इस धनराशि को जल्द से जल्द जारी करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बिलासपुर जिला के विकास के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। यहां के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए गोविंद सागर झील में जल क्रीड़ाओं से संबंधित गतिविधियां शुरू करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर के लिए 100 करोड़ रुपये की मल निकासी योजना का शिलान्यास जल्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने हिमाचल के अधिकारों को वापस दिलाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से बीबीएमबी की बिजली परियोजनाओं में हिमाचल को 12 प्रतिशत रॉयल्टी दिलाने में मदद करने का आग्रह किया। उन्होंनें कहा कि भाखड़ा बांध विस्थापितों की समस्याओं का समाधान करने के लिए राज्य सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के 20 लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए।

विधायक राजेश धर्माणी ने कहा कि इस वर्ष मानसून की बारिश से प्रदेश में व्यापक नुकसान हुआ है। जिला बिलासपुर में भी बादल फटने की घटनाएं देखने को मिली हैं। ऐसे कठिन समय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ग्राउंड जीरो पर पहुंचे आगे बढ़कर नेतृत्व प्रदान किया।

आपदा प्रभावितों को विशेष राहत पैकेज में ऐतिहासिक बढ़ौतरी के लिए ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इससे प्रभावितों को समय पर आवश्यक मदद सुनिश्चित हुई है। आपदा में प्रभावी कार्यो के लिए नीति आयोग, विश्व बैंक के साथ-साथ पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने भी मुख्यमंत्री की प्रशंसा की है।

पूर्व विधायक बीरू राम किशोर ने कहा कि आपदा के कारण प्रभावित परिवारों की पीड़ा को कम करते हुए सरकार बिना किसी भेदभाव के हर प्रभावित की मदद सुनिश्चित कर रही है। मुख्यमंत्री की प्रेरणा से सभी वर्ग आपदा प्रभावितों को राहत प्रदान करने के लिए आगे आ रहे हैं।

पूर्व विधायक बंबर ठाकुर ने कहा कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वयं राहत एवं बचाव कार्यो को नेतृत्व प्रदान किया। इस त्रासदी की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने विशेष राहत पैकेज जारी किया जिसमें मुआवजा राशि कई गुणा बढ़ाई गई है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को बड़े दिल वाला मुख्यमंत्री बताते हुए उन्होंने कहा कि वे राजनीति से ऊपर उठकर राज्य के हर आपदा प्रभावित को राहत राशि प्रदान कर रहे हैं।

पूर्व विधायक तिलक राज शर्मा ने बिलासपुर जिले में पुनर्वास योजना कार्यक्रम आयोजित करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया।

इससे पहले उपायुक्त आबिद हुसैन सादिक ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और जिला बिलासपुर में आपदा प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी।

इस अवसर पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंजना धीमान, कांग्रेस नेता विवेक कुमार नगर परिषद अध्यक्ष कमलेंद्र कश्यप सहित, जिला परिषद सदस्य गौरव शर्मा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री नई दिल्ली एम्स में भर्ती स्वास्थ्य स्थिति बेहतर

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में कुछ परीक्षणों के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया है। विभाग के डॉक्टरों की टीम ने उनके परीक्षण शुरू कर दिए हैं। इस प्रक्रिया में लगभग दो से तीन दिन लग सकते हैं। मुख्यमंत्री की सेहत पहले से बेहतर है, चिंता की कोई बात नहीं है।

वह डॉक्टरों की टीम की निगरानी में हैं। मेडिकल बुलेटिन के अनुसार ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की रिपोर्ट सामान्य हैं। मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य स्थिर है। उन्हें उचित आराम की जरूरत है, जिससे वह और तेजी से ठीक होंगे। आईजीएमसी शिमला के डॉक्टरों की सलाह पर मुख्यमंत्री को एम्स में भर्ती करवाया गया है।

गांव तक पहुंच गया है नशा, सख्त कदम उठाए पुलिस:कुलदीप राठौर

शिमला/शैल। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रवक्ता व ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि कि नशे का कारोबार प्रदेश में काफी ज्यादा बढ़ गया है। एनआईटी जैसे

संस्थान जहां काफी ज्यादा सख्ती होती है वहां भी छात्रावास तक नशा पहुंच गया है। यह अपने आप में चिंता व जांच का विषय है। शिमला में पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने सरकार से मांग की है कि इस मामले में सख्त कारवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह कारवाई दिखावे के लिए नहीं बल्कि असल में होनी चाहिए ताकि नशे के तस्करों पर लगाम लगाई जा सकें। राठौर ने कहा कि नशा आज ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपने पैर पसार चुका है। विधानसभा के मानसून सत्र में भी इस पर व्यापक चर्चा हुई थी। राज्य सरकार ने नशे पर लगाम लगाने के लिए कानून में संशोधन कर इसका प्रस्ताव मंजूरी के लिए केंद्र को भेजा है। अभी तक केंद्र से इस का कोई जवाब नहीं आया है। राठौर ने कहा कि यदि कोई बड़ा नेता भी इसमें संलिप्त है या आरोपी को बचाने की कोशिश करता है तो उस पर भी सख्त कारवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि राजधानी में भी पिछले कुछ समय से चिट्टे व अन्य नशे के मामलों में काफी बढ़ोतरी हुई है। यह भी चिंतनीय है, जब शिमला जो प्रदेश की राजधानी है वहीं पर नकेल नहीं कसी जा रही है तो दूर दराज क्षेत्रों में क्या हाल होगा। राठौर ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक इस मामले में छोटे तस्करों को ही पकड़ा गया है। बड़ी मच्छलियां अभी पकड़ से बाहर है।

नशा आने का मुख्य स्त्रोत क्या है, कहां से नशा आ रहा है उस पर जांच कर आरोपितों को पकड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस मामलें में केंद्रिय जांच एजेंसियों के साथ मिलकर कारवाई करने की जरूरत है। एक सवाल के जवाब में राठौर ने कहा कि प्रदेश के पांच राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनावों में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीतेगी। उन्होंने कहा कि वह भी जल्द मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए जा रहें है। मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर राठौर ने कहा कि उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। उम्मीद है कि जल्द वह स्वास्थ्य लाभ लेकर दोबारा प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए लौटेंगे।

ऑटो डीसीआर क्षमता के साथ विकसित होगा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का वेब पोर्टल: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में नियोजित एवं विनियमित विकास के दृष्टिगत राज्य सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सशक्त नेतृत्व में ठोस कदम उठा रही है। इसके लिए हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन के अंतर्गत नियमों में आवश्यक बदलाव किए गए हैं। साथ ही नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत इसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश के योजना क्षेत्रों के विनियमित विकास तथा लोगों को विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय के साथ कार्य करते हुए सरकार ने इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के वेब पोर्टल को ऑटो डीसीआर (विकास नियंत्रण विनियम) क्षमता के साथ विकसित किया जा रहा है। इससे योजना अनुमति के लिए प्रस्तुत नक्शों की कम्प्यूटरीकृत स्कैनिंग हो सकेगी। ऑटो डीसीआर एकमुश्त रिपोर्ट भी तैयार करेगा। आवेदक से संबंधित कमियों को जान सकेंगे और इनमें सुधार भी कर सकेंगे। इस वेब पोर्टल को ऑटो डीसीआर क्षमता के साथ विकसित करने का कार्य शीघ्र ही पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित गया है। इसमें पंजीकृत निजी पेशेवरों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, 500 वर्गमीटर तक के भू-खण्डों पर आवासीय उपयोग के लिए विकास अनुमति देने का कार्य भी शामिल है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में आवेदकों के आवागमन को सीमित करने के दृष्टिगत पंजीकृत निजी पेशेवरों के लिए अधिसूचित मानक संचालन प्रक्रिया जल्द ही विभाग के ऑनलाइन पोर्टल में शामिल करने के पश्चात शुरू कर दी जाएगी। यह केवल 500 वर्गमीटर के भू-खण्डों के आवासीय उपयोग के लिए सभी अधिसूचित योजना व विशेष क्षेत्रों तथा शहरी स्थानीय निकायों में विकास की अनुमति के लिए मान्य होंगी।

प्रदेश में फोरलेन के आसपास नियोजित एवं विनियमित विकास के दृष्टिगत फोरलेन योजना क्षेत्र का गठन भी किया गया है। फोरलेन योजना क्षेत्र में परवाणू-शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग, किरतपुर-मनाली, शिमला-मटौर तथा पठानकोट-मण्डी राजमार्ग शामिल हैं। इसके अतिरिक्त अटल सुरंग के उत्तरी पोर्टल में हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम नियोजन अधिनियम-1977 के प्रावधान लागू किए गए हैं। इससे सुरंग के संचालन के कारण संभावित अनाधिकृत और अनियोजित विकास गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा।

प्रदेश सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत पहुंचाने के दृष्टिगत एटिक के आवासीय उपयोग का भी प्रावधान किया है। इस संशोधन से भवनों के भीतर उपलब्ध स्थान में प्रभावी रूप से बढ़ोतरी होगी। साथ ही अतिरिक्त मंजिलें बनाने में लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ भी मिल सकेगा।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशों पर भविष्य में भवनों की जल निकासी प्रणाली की जांच तथा इमारतों के संरचनात्मक डिजाइन के बारे में विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है। इससे बरसात के दौरान राज्य में भारी बारिश के कारण सार्वजनिक और निजी सम्पत्ति को होने वाले नुकसान को नियंत्रित एवं सीमित करने में सहायता मिल सकेगी।

नौणी विवि की वानिकी के दो छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन

शिमला/शैल। डॉ. यशवंत सिंह परमार औदयानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी के सिल्विकल्चर

साक्षी तोमर

और एग्रोफोरेस्ट्री विभाग से एमएससी उतीर्ण कर चुकी छात्रा साक्षी तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा वानिकी के विषय के लिए आयोजित आईसीएआर-ए.आई.सी.ई.-जेआरएफ/एसआरएफ-2023 परीक्षा में देश भर में शीर्ष रैंक हासिल किया है। इसके अतिरिक्त साक्षी ने वानिकी में पीएचडी कार्यक्रम में प्रवेश के लिए यूपी राज्य पात्रता परीक्षा में भी पहला स्थान हासिल किया है। साक्षी ने सिल्विकल्चर और एग्रोफोरेस्ट्री विभाग के प्रोफेसर और विभाग अध्यक्ष डॉ. डीआर भारद्वाज की मागदर्शन में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की है।

इसी विभाग की पीएचडी छात्रा मिताली मेहता को भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (आई. सी.

मिताली मेहता

एफ. आर.ई), देहरादून में वैज्ञानिक -बी के पद पर चयन हुआ है। मिताली को असम के जोरहाट स्थित रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीटयूट में नियुक्ति मिली है। मिताली ने नौणी से बीएससी और पीएचडी की डिग्री पूरी की है। मिताली ने डॉक्टरेट की पढ़ाई डॉ. के.एस.पंत के मार्गदर्शन में पूरी हुई।

विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल, वानिकी महाविद्यालय के डीन डॉ. सीएल ठाकुर और एसएएफ विभाग के वैज्ञानिकों और छात्रों ने साक्षी और मिताली को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं।

तुम्हे अन्दर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हे पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हे आध्यात्मिक नहीं बना सकता। तुम्हारी आत्मा के आलावा कोई और गुरु नहीं है।
..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

अब अधिकारी होंगे रथ प्रभारी

मोदी सरकार अपने नौ वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां को लेकर एक विकसित भारत संकल्प यात्रा कर रही है। यह यात्रा देश के 765 जिलों की 2.69 लाख पंचायतों से होकर गुजरेगी। 2014 से अब तक जो उपलब्धियां इस सरकार की रही है उन्हें इस यात्रा के माध्यम से देश के सामने रखा जाएगा। हर रथ एक उपलब्धि का वाहक होगा और उसका प्रभारी एक भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होगा। अक्तूबर 2022 में इस योजना की रूपरेखा तैयार की गयी थी। अब अक्तूबर 2023 में एक प्रपत्र के माध्यम से इन प्रभारियों के नाम मांगे गये। इसमें उपनिदेशक से लेकर संयुक्त सचिव स्तर तक के अधिकारियों को रथ प्रभारी नामित किया जाएगा। इससे पूर्व रक्षा मंत्रालय ने भी छुट्टी पर जाने वाले सैनिकों से भी कहा है कि उन्हें राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में हिस्सा लेना चाहिए इसके लिए स्थानीय समुदाय से जुड़कर सरकारी योजनाओं का प्रचार करना चाहिए। यह यात्रा 25 नवम्बर 2023 से 25 जनवरी 2024 तक जारी रहेगी। कई राजनीतिक दलों ने इस योजना का विरोध करते हुए इसे अधिकारियों का राजनीतिकरण किया जाने की संज्ञा दी है। चुनाव आयोग ने भी इसका संज्ञान लेकर जिन राज्यों में अभी चुनाव हो रहे हैं और वहां पर आचार संहिता लागू हो चुकी है वहां पर इसके प्रवेश पर रोक लगा दी है। अब इस मुद्दे पर एक अलग बहस छिड़ गई है क्योंकि जहां कांग्रेस और अन्य दल इसका विरोध कर रहे हैं वहीं पर भाजपा इसका पुरजोर समर्थन कर रही है। जब सरकार पिछले एक वर्ष से इस योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है तो निश्चित है कि यह लागू होगी। भले ही रथ प्रभारी के स्थान पर इन अधिकारियों को नोडल अधिकारी का पदनाम दे दिया जाये। यहां पर यह भी स्मरणीय है कि मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र से तीन दर्जन से भी अधिक कॉर्पोरेट अधिकारियों को यू.पी.एस.सी. पास किए बिना ही सीधे आई.ए.एस. संयूक्त सचिव नामित कर दिया और उस पर आई.ए.एस. द्वारा कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी गई थी। क्योंकि सरकार ऐसा कर सकती है। शायद इसी मौन का परिणाम है कि आज आई.ए.एस. अधिकारियों को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए रथ प्रभारी नामित किया जा रहा है। संभव है कि इसके बाद देश प्रतिबद्ध कार्यपालिका की ओर भी बढ़ जाये। सविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका और व्यवस्थापिका तीनों को स्वतंत्र रखा गया है। कार्यपालिका के लिए तो सेवा नियम 1964 अलग से परिभाषित है और अपेक्षा की जाती है कि कार्यपालिका राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रहे। क्योंकि राजनीतिक सता तो हर पांच वर्ष बाद बदल जाती है। इसीलिए कार्यपालिका को 60 वर्ष की आयु तक का कार्यकाल दिया गया है ताकि उसकी निरन्तरता में सता बदलने का कोई प्रभाव न पड़े। इसलिए नीति और नियम बनाने का काम व्यवस्थापिका को दिया गया है। इन नीति नियमों की अनुपालना कार्यपालिका के जिम्मे है। ऐसे में जब राजनीतिक सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं के प्रचार प्रसार की ऐसी जिम्मेदारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को दी जाएगी तो उनकी निष्पक्षता कितनी बनी रह पाएगी यह अपने में ही एक बड़ा सवाल बन जाएगा। सरकार के ऐसे फैसलों पर वरिष्ठ नौकरशाही की ओर से ऐतराज़ आना चाहिए था। लेकिन जब कैबिनेट सचिव स्तर से लेकर कई राज्यों के मुख्य सचिव तक सेवा विस्तारों पर चल रहे हो तो फिर कार्यपालिका की निष्पक्षता कैसे सुरक्षित रह पाएगी?

नकारात्मक राजनीति से परहेज कर उज्जवल भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें

गौतम चौधरी

एक मुसलमान अपने प्रयासों के हर पहलू में, सामान्य से लेकर विशेष तक, कुरान और सुन्नत की शिक्षाओं का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अल्लाह के नवी, पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उम्माह यानी मानने वालों को गहन ज्ञान प्रदान किया। उन्हें विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान दिया, जो उन्हें वर्तमान जीवन के अस्तित्व में विजय और जीवन के बाद शाश्वत आनंद की ओर ले जाएगा। साथ ही, उन्होंने उन्हें ऐसे किसी भी कार्य या मामले के प्रति आगाह किया जो उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और उन्हें नरक के खतरों की ओर ले जा सकता है। पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तेरह वर्षों की अवधि तक अपने समर्पित साथियों के साथ कई प्रकार के उत्पीड़न झेले, बावजूद इसके मुसलमानों को मक्का की सीमाओं के भीतर सार्वजनिक प्रदर्शनों में शामिल होने से रोका। उन्होंने सड़कों को अवरुद्ध करने, सविनय अवज्ञा के कृत्यों में शामिल होने, या लक्षित हत्याओं के कृत्यों को अंजाम देने की साजिश से परहेज किया। यह कोई साधारण बात नहीं है। अन्य धार्मिक चिंतन में इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं।

विपरीत परिस्थितियों में धैर्य व्यक्ति का सच्चा साथी होता है। पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को भली–भांति समझते थे। मुहम्मद के सारे संदेश अरबी में हैं। इसलिए उसकी व्याख्या कर इस्लामिक विद्वान लोगों को बताते हैं। ऐसे ही विद्वानों में से एक मोहम्मद आलम साहब हैं। उनका मानना है, ''यदि आप किसी सत्ता के खिलाफ संघर्ष करते हैं तो वह आपको किसी कीमत पर नहीं छोड़ेगा और उस सत्ता के उत्पीड़न का आपको सामना करना ही पड़ेगा। इस्लाम इस मामले में साफ–साफ ख्याल रखता है। सत्ता यदि दीन वालों की हो तो वहां सरिया का कानून होगा और उसमें किसी प्रकार के उत्पीड़न की कोई गुंजाइस नहीं होती है। जहां इस्लामिक कायदे कायम नहीं होते हैं और वहां बेवजह किसी का उत्पीड़न होता है, तो इस्लाम में उसके प्रतिकार की बात कही गयी है, लेकिन उस प्रतिकार की अपनी धार्मिक व्याख्या है। इस्लाम के अनुसार उस प्रतिकार की अपनी शैली भी है। जहां इस्लाम के कायदे नहीं हैं, लेकिन जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है, साथ ही इस्लामिक कायदों को अपनाने की छूट दी गयी है, वहां इस्लाम का संदेश है कि ईमान वाले अन्य लोगों के साथ घुलमिल कर रहें और शासन को कानून का राज कायम करने में सहयोग दें। लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष शासन प्रणाली में इस्लामी सिद्धांत के अनुसार, विरोध प्रदर्शनों, प्रदर्शनों में शामिल होना और शासकों के अधिकार को चुनौती देना गलत और अनुमति योग्य नहीं माना गया है।

इसके अलावा, मुसलमानों के लिए ऐसी रणनीतियों को अपनाना अनिवार्य है जो उन्हें नौकरशाही कार्यालयों के माध्यम से शासन संरचनाओं में समायोजित करती हैं और समुदाय के लिए फायदेमंद नीतियों की वकालत करती हैं। मुसलमानों को अपने विकासात्मक, आर्थिक और शैक्षिक पिछड़ेपन को उजागर करने के लिए नागरिक समाज में शामिल होने या मीडिया का उपयोग करने जैसे रचनात्मक उपायों को अपनाने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त, यह बात जानना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक–राजनीतिक जागरूकता और संवैधानिक अधिकारों एवं कानूनी ज्ञान द्वारा विभिन्न कमियों को दूर किया जा सकता है। विशेष रूप से मुस्लिम छात्रों को अपने समुदाय को शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने विचारों और चेतना को सुव्यवस्थित करने के लिए बाध्य करना होगा और उन गतिविधियों से बचना होगा जो उनके और समुदाय के लिए प्रतिकूल हैं। हम सब इस बात से वाकफ हैं कि किसी दुश्मन देश के षडयंत्रकारी, गुप्तचर अपने दुश्मन देश को अस्थिर करने की पूरी योजना बनाती रहती है। इस षडयंत्र में फंसना अपने भविष्य के साथ तो खिलवाड़ करना है ही यह इस्लाम के मूल सिद्धांतों के भी खिलाफ है।

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन यानी एएमयूओबीए के दिल्ली चैप्टर के अध्यक्ष मुदस्सिर हयात ने हाल ही में एक ब्यान जारी कर जामिया मिलिया इस्लामी और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों से भविष्य में किसी भी तरह के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से परहेज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने नूंह हिंसा के बाद ब्यान जारी किया। उनका ब्यान इस बिंदु पर केंद्रित था कि असंगठित हिंसक विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के बजाये विश्वसनीय नेतृत्व के साथ रहना और अपनी आवाज बुलंद करना बेहतर है। असंगठित हिंसक विरोध न केवल इस्लामी शिक्षाओं के खिलाफ है, बल्कि कानूनों के भी खिलाफ है।

देश के मुस्लिम युवाओं को पुराने वाक्यांश को याद रखने की जरूरत है कि कलम तलवार से अधिक शक्तिशाली होता है। आइए कलम से लड़ें और नकारात्मक राजनीति से प्रेरित इरादे रखने वालों के लिए तलवार छोड़ दें। आइए यह कभी न भूलें कि पैगंबर मुहम्मद के पास सेना होने के बावजूद हुदैबिया संधि पर सहमत हुए थे, क्योंकि उन्होंने हिंसा पर शांति को प्राथमिकता दी। आइए नकारात्मक राजनीतिक जाल में न फंसें और उज्ज्वल भविष्य पर अपना ध्यान केंद्रित करें।

भारतीय पैरा–एथलीटों ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे अधिक पदकों के साथ इतिहास रचा

शिमला। भारतीय पैरा–एथलीटों ने एशियाई पैरा खेलों में भारत के अब तक के सबसे अधिक पदकों के साथ इतिहास रच दिया है। उन्होंने 29 स्वर्ण पदकों सहित कुल 111 पदक जीते। इससे पहले भारत ने एशियाई पैरा खेलों के 2010 संस्करण में 14 पदक, 2014 में 33 और 2018 में 72 पदक जीते थे। इन खेलों की शुरुआत के बाद से यह भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है, जहां भारत समग्र पदक तालिका में पांचवें स्थान पर रहा। भारत ने इस वर्ष अपना सबसे बड़ा दल भेजा था, जिसमें 303 एथलीट (191 पुरुष और 112 महिला) शामिल थे। कुल 111 पदकों में से महिला एथलीटों ने 40 पदकों का योगदान दिया है, यानी कुल पदकों में 36 प्रतिशत की हिस्सेदारी की।

इस रिकॉर्ड–तोड़ प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए, केन्द्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा, 'यह प्रदर्शन हमारे एथलीटों की कड़ी मेहनत और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में खेलों से जुड़ी सही नीतियों की शुरूआत को दर्शाता है। चाहे वह जमीनी स्तर पर खेलो इंडिया योजना हो या सर्वोत्कृष्ट एथलीटों से संबंधित टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना, इन योजनाओं के माध्यम से दिया गया समर्थन वास्तव में अब परिणाम देने लगा है। आपको यह जानकर खुशी होगी कि 8 खेलो इंडिया एथलीटों और 46 टॉप्स एथलीटों ने इन खेलों में भाग लिया और 111 पदकों में से कुल 38 पदक जीते। साथ ही, 2014 की तुलना में खेल बजट में तीन गुना वृद्धि ने भी हमें अपने सभी एथलीटों को बेहतर समर्थन प्रदान देने की क्षमता दी है, चाहे वह प्रशिक्षकों के मामले में हो या फिर प्रशिक्षण, विदेश में अनुभव हासिल करने, आहार, बुनियादी ढांचे के संदर्भ में।'

उन्होंने कहा, 'हाल ही में संपन्न एशियाई खेलों के साथ–साथ इन एशियाई पैरा खेलों और पिछले ओलंपिक, पैरालंपिक, सीडब्ल्यूजी, डेफ्लंपिक्स में एथलीटों का शानदार प्रदर्शन यह दर्शाता है कि खेलों में भारत की शक्ति बढ़ रही है। और जैसाकि माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में आईओसी की बैठक में कहा, भारत न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर रहा है बल्कि बड़े आयोजनों की मेजबानी के लिए भी तैयार है, चाहे वह 2030 में युवा ओलंपिक हो या 2036 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक।

शिक्षा क्षेत्र में भविष्योन्मुखी पाठ्यक्रम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही प्रदेश सरकार

17 आईटीआई में आधुनिक व प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू

विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में 2069 प्रशिक्षणार्थियों को मिला रोजगार

शिमला। बदलते परिवेश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते उपयोग से इस क्षेत्र से संबंधित नए पाठयक्रम शुरू करना समय की मांग है। वर्तमान प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में शिक्षा क्षेत्र में अत्याधुनिक पाठयक्रम शुरू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री का मानना है कि आधुनिक व भविष्योन्मुखी विषयों से संबंधित शिक्षा से युवाओं को रोजगार व स्वरोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनकी ऊर्जा का भी बेहतर दोहन किया जा सकता है।

इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैक्ट्रोनिक्स, सौर टैक्निशियन तथा इलैक्ट्रिक व्हीकल मैकेनिक जैसे नए क्षेत्रों में रोजगार व स्वरोजगार की अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इन क्षेत्रों में युवाओं को शिक्षित व प्रशिक्षित करने के लिए विशेष प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। इसी का परिणाम है कि वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के 17 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आधुनिक प्रासंगिक व्यवसायों की 19 इकाइयां शुरू की गई हैं। इनमें आईटीआई रैल, ऊना, पालमपुर, शाहपुर और नगरोटा बगवां में इंटरनेट ऑफ थिंग्स टैक्निशियन (स्मार्ट सिटी) विषय शुरू किया गया है। इसी प्रकार आईटीआई रैल, पंडोगा, नाहन, गरनोटा और प्रगतिनगर में मैकेनिक इलैक्ट्रिकल व्हीकल, आईटीआई घुमारवीं एवं अर्की में फाइबर टू होम टैक्निशियन, आईटीआई सुन्नी व शाहपुर में टैक्निशियन मैट्रोनिक्स, आईटीआई जुब्बल, सुन्दरनगर (पीडब्ल्यूडी), शमशी और बालकरूपी में सौर टैक्निशियन (इलैक्ट्रिकल) तथा आईटीआई नालागढ़ में मैंटेनेंस मैकेनिक (रसायनिक संयंत्र) की इकाइयां शुरू की गई हैं।

प्रदेश सरकार हिमाचल को हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसके लिए विद्युत चालित वाहनों के अधिकाधिक उपयोग तथा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए युवाओं को प्रोत्साहन प्रदान किया जा रहा है। इस तरह के नए पाठयक्रम शुरू होने से इन क्षेत्रों में विशेषज्ञ व प्रशिक्षित मानव संसाधन प्रदेश में ही उपलब्ध हो सकेगा।

महाविद्यालय स्तर पर भी नए पाठयक्रमों के माध्यम से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है। राजकीय हाईड्रो इंजीनियरिंग महाविद्यालय बंदला में कंप्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डाटा साइंस), राजकीय बहुतकनीकी संस्थान रोहडू में कंप्यूटर इंजीनियंरिग एवं आइईओटी डिप्लोमा कोर्स तथा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान चम्बा में मैक्ट्रोनिक्स डिप्लोमा कोर्स शैक्षणिक सत्र 2023-24 से आरंभ कर दिए गए हैं। इनमें लगभग शत-प्रतिशत प्रवेश दर्ज हुआ है। इसके अतिरिक्त अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रगतिनगर में इलैक्ट्रॉनिक्स एवं कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कोर्स इसी शैक्षणिक सत्र से आरंभ किया गया है।

युवाओं के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं भी सफलतापूर्वक क्रियान्वित की जा रही हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साथ मिलकर उन्हें शैक्षणिक आदान-प्रदान का अवसर भी प्रदान किया जा रहा है। राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों के 38 बच्चों तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों व बहुतकनीकी संस्थानों के 20 संकाय को आईआईटी मंडी में एक सप्ताह का रोबोटिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजों के 20 संकाय को सेमीकंडक्टर इको सिस्टम के लिए आईआईटी रोपड़ एवं दिल्ली भेजा गया है। राजकीय बहुतकनीकी एवं इंजीनियरिंग के 10 संकाय एवं 10 छात्र-छात्राओं को भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ऊना में पांच दिन के मशीन लर्निंग एवं एप्लीकेशन में आधुनिक विकास कोर्स के लिए भेजा गया। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 44 प्रशिक्षुओं को नियुक्त किया गया है।

पाठयक्रम पूरा होने के उपरांत युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के दृष्टिगत भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों, फार्मेसी महाविद्यालयों, बहुतकनीकी और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों से लगभग 2069 प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न औद्योगिक इकाईयों में रोजगार मेले, कैंपस साक्षात्कार व संयुक्त कैंपस साक्षात्कार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध करवाए गए हैं।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि प्रदेश के युवा ऊर्जा एवं उत्साह से भरपूर हैं और उन्हें भविष्योन्मुखी पाठयक्रमों से जोड़ते हुए पारंगत करने की आवश्यकता है। इससे वे स्वयं तो रोजगार व स्वरोजगार प्राप्त कर ही सकते हैं, वहीं प्रदेश के तीव्र विकास में भी अपना उल्लेखनीय योगदान देने की लिए सक्षम बन सकेंगे।

वन प्रबंधन समितियों को केंचुआ खाद के माध्यम से रोजगार के अच्छे अवसर

-खेमचंद चौहान-
जिला लोक संपर्क अधिकारी चम्बा

केंचुआ खाद या वर्मीकम्पोस्ट पोषण पदार्थों से भरपूर एक उत्तम जैव जैव उर्वरक है। यह केंचुआ आदि कीड़ों के द्वारा वनस्पतियों एवं भोजन के कचरे आदि को विघटित करके बनाई जाती है। जिसमें बदबू न होने के साथ-साथ मक्खी एवं मच्छर नहीं बढ़ते है तथा वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। तापमान नियंत्रित रहने से जीवाणु क्रियाशील तथा सक्रिय रहते हैं।

यह भूमि की उर्वरकता, वातायनता को तो बढ़ाता है साथ ही भूमि की जल सोखने की क्षमता में भी वृद्धि करता हैं। वर्मी कम्पोस्ट से अधिक पैदावार,भूमि में खरपतवार कम उगते हैं तथा पौधों में कम रोग लगते हैं और पौधों तथा भूमि के बीच आयनों के आदान प्रदान में वृद्धि होती हैं।

वन मंडल अधिकारी चंबा रजनीश महाजन केंचुआ खाद के संदर्भ में जानकारी देते हुए बताते हैं कि केएफडब्ल्यू से वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना है। जिसके अंतर्गत जिला में 38 ग्रामीण वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया है। गठित की गई ग्रामीण वन समितियां के द्वारा प्रवेश बिंदु गतिविधियां जिसे आमदनी अर्जित गतिविधियां भी कहा जाता है के तहत जिला में केंचुआ खाद बनाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि परियोजना के अंतर्गत जिला में द्रमंण,ओड़ा और टपून सोसाइटी गठित की गई है जिनके द्वारा वन विभाग के सहयोग से केंचुआ खाद तैयार की जा रही है। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा चलाई गई योजना एक बूटा बेटी के नाम के तहत आयोजित की जा रही विभिन्न गतिविधियों के लिए वन मंडल चंबा और डलहौजी के द्वारा इस केंचुआ खाद को उपयोग में लाया जा रहा है। इसके अलावा केंचुए खाद को प्रदेश के अन्य जिलों में भी बेचा जा रहा है। जिससे गठित की गई वन प्रबंधन समितियों को केंचुआ खाद के माध्यम से रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होने के साथ उनकी आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार हो रहा है।

ग्रामीण वन प्रबंधन समिति द्रमंण की सुनो का कहना है कि वन विभाग के सहयोग से ग्राम पंचायत ब्राह्मण के गांव काथला में हिमाचल प्रदेश वन परिस्थितिकी तंत्र जलवायु प्रूफिंग परियोजना के तहत ग्रामीण वन प्रबंधन समिति गठित की गई है जो सामूहिक तौर पर केंचुआ खाद तैयार कर रही है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की ओर खाद को तैयार करने

वाले पिट के निर्माण के लिए विभाग की ओर से 1 लाख 30 अनुदान राशि प्रदान की गई थी। उन्होंने बताया कि केंचुआ खाद तैयार करने के लिए बान, गुलाबी बराश के अलावा उपलब्ध अन्य पेड़ों की सूखी पत्तियों के साथ गोबर का घोल बनाकर पिट में डाल दिया जाता है और खाद में डाले जाने वाले केंचुए जो वन विभाग की ओर से उपलब्ध करवाए जाते हैं के साथ पिट को ढक दिया जाता है। उन्होंने बताया कि ढके गए पिट में तीन माह के भीतर केंचुआ खाद तैयार हो जाती है।

उन्होंने बताया कि 10 लोग सामूहिक तौर पर इस कार्य को कर रहे हैं। गत वर्ष में समिति द्वारा लगभग 105 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट केंचुआ खाद तैयार की है। तैयार की गई केंचुआ खाद को वन मंडल चंबा और डलहौजी के अलावा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में 10 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचा जा रहा है।

समिति के प्रधान सुनो देवी ने बताया कि तैयार की जा रही वर्मीकंपोस्ट केंचुआ खाद से सोसाइटी से जुड़े सभी लोगों को अच्छी आमदनी अर्जित हो रही है।

शहीद सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की दरों में सम्मानजनक वृद्धि

भूतपूर्व सैनिकों को बुढ़ापा पेंशन के लिए 35 हजार रुपये की आय सीमा समाप्त

365 शौर्य पुरस्कार और उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को 73 ,93 ,975 रुपये की राशि वितरित

शिमला। हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ-साथ वीरभूमि भी कहा जाता है। प्रदेश से हजारों युवा देश की सरहदों की रक्षा के लिए सेना में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। वीर सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। वर्तमान प्रदेश सरकार ने युद्ध अथवा सैन्य ऑपरेशन के समय हुए शहीद या दिव्यांग सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि की दरों में सम्मानजनक वृद्धि की है।

युद्ध या युद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक, जिनमें सशस्त्र सेना व अर्द्धसैनिक बलों के जवान शामिल हैं, उन्हें पूर्व में प्रदत्त 20 लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 30 लाख रुपये किया गया है। इसी प्रकार बीमारी या किन्हीं अन्य कारणों से मृत्यु की स्थिति में सैनिक के आश्रितों को प्रदत्त अनुग्रह राशि को 05 लाख रुपये से बढ़ाकर 7.50 लाख रुपये किया गया है। 50 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले सैनिक जो इस कारण सेवानिवृत्त हुए हों, उन्हें दी जाने वाली अनुग्रह राशि को 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 3.75 लाख रुपये किया गया है। 50 प्रतिशत से कम की दिव्यांगता वाले सैनिक जो इन्हीं कारणों से सेवानिवृत्त हुए हों, उन्हें पूर्व में प्रदत्त एक लाख रुपये की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1.50 लाख रुपये किया गया है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अभी तक 22 लाभार्थियों को 2 करोड़ 22 लाख रुपये की अनुग्रह राशि वितरित की गई है।

प्रदेश सरकार विभिन्न शौर्य पुरस्कारों से सम्मानित भूतपूर्व सैनिकों को उनकी बहादुरी के सम्मान में नकद पुरस्कार, वार्षिकी व भूमि की एवज़ में नकद राशि प्रदान करती है। शौर्य पुरस्कार और उत्कृष्ट सेवा पुरस्कार विजेताओं को यह राशि प्रदान की जा रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक 365 लाभार्थियों को 73,93,975 रुपये की राशि वितरित की गई है।

पूर्व सैनिकों के पुनरुत्थान व पुनर्वास के लिए भी विशेष निधि के तहत विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। पूर्व सैनिकों एवं उनके बच्चों को विशेष निधि के अन्तर्गत विभिन्न छात्रवृत्तियां प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए वार्षिक आय की अधिकतम सीमा 07 लाख रुपये निर्धारित की गई है। यह छात्रवृत्तियां स्नातकोत्तर पाठयक्रम, बहुतकनीकी व कृषि विश्वविद्यालय, मेडिकल व इंजीनियरिंग तथा आयुर्वेद जैसे व्यावसायिक पाठयक्रम सहित आईटीआई व अन्य ऐसे ही पाठयक्रमों के लिए प्रदान की जाती हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार में 15 प्रतिशत आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है। पद के लिए पात्रता और योग्यता अनुसार पूर्व सैनिक उपलब्ध नहीं होने पर अधिसूचना के 02 वर्ष बाद ऐसे पदों का अप्राप्यता प्रमाण पत्र संबंधित विभाग को दिया जाता है। इसके उपरांत संबंधित विभाग द्वारा नियमावली के अनुसार इन पदों पर पूर्व सैनिकों के बच्चों की नियुक्ति की जाती है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस वर्ष अभी तक 300 पूर्व सैनिकों अथवा उनके आश्रितों को नियुक्तियां प्रदान की गई हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा युद्ध विधवाओं की पुत्री की शादी के लिए 50 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता केवल दो पुत्रियों के लिए लागू है। ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें किसी प्रकार की पेंशन नहीं मिलती तथा जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, इस श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को 3000 रुपये प्रतिमाह तथा द्वितीय विश्व युद्ध के भूतपूर्व सैनिकों अथवा उनकी विधवाओं को क्रमश: 10000 व 5000 रुपये प्रतिमाह वृद्धावस्था पेंशन बतौर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। वर्तमान प्रदेश सरकार द्वारा इस वित्त वर्ष में अभी तक 1162 लाभार्थियों को एक करोड़ 48 लाख 34 हजार 969 रुपये के लाभ प्रदान किए गए हैं। वर्तमान सरकार ने बुढ़ापा पेंशन के लिए 35 हजार रुपये की आय सीमा को भी 02 सितम्बर, 2023 से समाप्त कर दिया है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि हमारे वीर सैनिक देश की सरहदों को सुरक्षित रखने में अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी कारण हम सभी स्वयं को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। प्रदेश सरकार इन वीर जवानों, पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरने का प्रावधान अपने प्रथम बजट में ही किया है।

सांसद ने 22 लाख से निर्मित एम्बूलैंस रोड़ का किया उद्घाटन

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं सांसद मण्डी संसदीय क्षेत्र प्रतिभा सिंह ने सदर विधानसभा क्षेत्र के पंजहेटी में 22 लाख की लागत से

निर्मित एम्बुलैंस रोड़ पंजेहटी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस का दूसरा नाम ही विकास है और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह ने प्रदेश को संवारा है। उन्होंने कहा प्रदेश का हर गांव सड़क सुविधा से जुड़ा है साथ ही हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में भी अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा के समय कांग्रेस सरकार सभी प्रभावित लोगों की हरसंभव मदद कर रही है। प्रतिभा सिंह ने जन समूहों को संबोधित करते हुए कहा कि सड़क निर्माण से समूचे क्षेत्र का विकास होता है। उन्होंने लोगों से विकास कार्यो में बढ़-चढ़ कर भाग लेने का आग्रह किया । उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पंजेठी सबसे बेहतर सडक बनी है जिसका बड़ी आबादी को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा की जब-जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकारें रही है तब तब हिमाचल प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का न केवल विस्तारीकरण हुआ बल्कि इनकी पहुंच प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों तक भी सुनिश्चित हुई है। सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा कि पिछले दिनों प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के चलते प्रदेश वासियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। उन्होंने कहा कि आपदा में पीड़ितों की मदद को प्रदेश ने लगातार केंद्र सरकार से इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की जा रही है। बावजूद इसके केन्द्र सरकार ने अब तक इस दिशा में कोई ठोस प्रयास नहीं किए हैं।

फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण

शिमला/शैल। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश के सभी 68 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लोक सभा और विधान सभा निर्वाचनों के लिए प्रयुक्त होने वाली फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का प्रथम जनवरी, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार पर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करवाया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि फोटोयुक्त सूचियों का प्रारूप प्रकाशन 27 अक्तूबर, 2023 को हिमाचल प्रदेश में स्थापित प्रत्येक मतदान केन्द्र तथा सम्बन्धित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एडीएम, एसडीएम) सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्धतहसीलदार, नायब तहसीलदार के कार्यालयों में किया गया है। प्रारूप फोटोयुक्त मतदाता सूचियां 27 अक्तूबर, 2023 से 09 दिसम्बर 2023 तक उपरोक्त स्थलों पर जन साधारण के नि:शुल्क निरीक्षण तथा दावे और आक्षेप समुचित फार्म 6, 7 व 8 पर दर्ज करने के लिए उपलब्ध रहेगी। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की अहर्ता तिथि प्रथम जनवरी 2024 है, लेकिन जो भी पात्र नागरिक प्रथम अक्तूबर, 2024 तक 18 वर्ष की आयु का हो जायेगा, वह भी मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। उक्त पुनरीक्षण के दौरान केवल प्रथम जनवरी, 2024 की अहर्ता तिथि के आधार प्राप्त दावों का निपटारा ही किया जायेगा और अग्रिम आवेदनों का निपटारा मतदाता की आयु 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित अहर्ता तिथियों प्रथम अप्रैल, 2024, प्रथम जुलाई, 2024 तथा प्रथम अक्तूबर, 2024 के आधार पर किया जायेगा। अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए निर्वाचन विभाग के नि:शुल्क टेलीफोन सेवा कॉल सेन्टर 1950 पर कार्यालय समयावधि प्रात: 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक लैण्डलाईन या मोबाईल फोन से सम्पर्क किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि जन साधारण की सुविधा के लिए प्रत्येक मतदान केन्द्र पर 04 व 05 नवम्बर, 2023 तथा 18 व 19 नवम्बर 2023 को विशेष अभियान दिवस निर्धारित किये गए हैं ताकि सभी छूटे हुए पात्र नागरिक अपना अथवा अपने परिवार के पात्र व्यक्ति का नाम फोटोयुक्त मतदाता सूची में दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धि करवाने तथा परिवार के अपात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाया जाना सुनिश्चित कर सकें। दावों व आक्षेपों का निपटारा 26 दिसम्बर, 2023 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी, 2024 को किया जाएगा।

वर्तमान मतदाता सूचियों में कोई भी पात्र नागरिक अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि इन्टरनेट वेबसाईट http://ceohimachal.nic.in में भी कर सकता है। वेबसाईट व राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल (एनवीएसपी) पर भी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन फार्म (नाम दर्ज करने, अपमार्जन तथा संशोधन के लिए) भरे जा सकते हैं।

इस संबंध में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से चन्द्र शेखर शर्मा तथा आम आदमी पार्टी से दलीप सिंह उपस्थित रहे। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को फोटोयुक्त मतदाता सूचियों के उपरोक्त विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम और वैद्यानिक प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गई।

उन्हें अवगत करवाया गया कि प्रदेश में वर्तमान में कुल 7990 मतदान केन्द्र हैं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 6751, भारतीय जनता पार्टी द्वारा 7164, बहुजन समाज पार्टी द्वारा 91, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी) द्वारा 40 तथा आम आदमी पार्टी द्वारा 124 बूथ लेबल ऐजेन्ट नियुक्त किए गए हैं। जबकि नेशनल पीपुल्स पार्टी द्वारा कोई भी बूथ लेबल ऐजेन्ट नियुक्त नहीं किया है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनैतिक दलों से आग्रह किया कि वे प्रत्येक मतदान केन्द्र पर अपना बूथ लेवल ऐजेन्ट नियुक्त करें।

उन्होंने सभी नागरिकों, स्थानीय राजनैतिक दलों, गैर सरकारी स्वयंसेवी संगठनों, महिला एवं युवा मण्डलों से आग्रह किया कि प्रारूप प्रकाशन की अवधि 27 अक्तूबर, 2023 से 09 दिसंबर, 2023 तक फोटोयुक्त मतदाता सूचियों का निरीक्षण अपने सम्बन्धित मतदान केन्द्र पर जाकर अवश्य करें और पात्र नागरिकों के नाम दर्ज करवाने, अशुद्ध प्रविष्टियों में शुद्धि करवाने तथा अपात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटवाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें ताकि फोटोयुक्त मतदाता सूचियों को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाया जा सके।

हिमाचल में शुरू होगी टूरिस्ट हेल्पलाइन:आर.एस.बाली

शिमला/शैल। पर्यटन निगम के अध्यक्ष कैबिनेट रैंक आरएस बाली ने कहा कि राज्य में पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ किया जा रहा है और सैलानियों की सुविधा के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुविधा के लिए शीघ्र ही टूरिस्ट हेल्पलाइन भी शुरू की जाएगी और इसे 1100 हेल्पलाइन से जोड़ने पर भी विचार किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क सम्पर्क के साथ-साथ हवाई सेवाएं भी सुदृढ़ की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह प्रयास किया जा रहा है कि प्रदेश के पर्यटन गंतव्यों में पर्यटकों का अधिक दिन तक ठहराव हो। इसके लिए कि प्रदेश सरकार राज्य में ईको-टूरिज्म पर्यटन को व्यापक स्तर पर प्रोत्साहित कर रही है और इसके लिए आवश्यक अधोसंरचना विकसित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण वन क्षेत्रों में 11 ईको-पर्यटन स्थल चिन्हित किए गए हैं। इनमें पालमपुर वन मंडल में स्वार, सौरभ वन विहार, न्यूगल पार्क, बीड़-बिलिंग, पार्वती वन मंडल में कसोल, खीर गंगा व सुमारूपा, सिराज में सोझा, कोटगढ़ में नारकंडा और शिमला वन मंडल के तहत शोघी कैंपिंग स्थल व पोटर हिल कैंपिंग स्थल शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य में पर्यटकों को वैश्विक स्तर की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार वचनबद्ध है। इसी दिशा में अनेक नवोन्मेषी पहल की जा रही हैं। प्रदेशवासियों और पर्यटकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए चरणबद्ध तरीके से यू.वी.अल्ट्रा फिल्टरेशन तकनीक का उपयोग किया जाएगा।

पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप का शुभारम्भ

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष आर.एस. बाली वर्चुअल माध्यम से जिला कांगड़ा के बीड़-बिलिंग में आयोजित पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप के शुभारम्भ अवसर पर सम्मिलित हुए।

मुख्य संसदीय सचिव किशोरी लाल ने बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडर को हरी झंडी दिखाकर इस आयोजन

का शुभारम्भ किया।

आर.एस. बाली ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने का संकल्प लिया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश विश्व में पसंदीदा गंतव्य के रूप में प्रसिद्ध है। राज्य में अनेक मनोरम व लुभावने पर्यटक स्थल हैं। प्रदेश पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप की मेज़बानी कर रहा है जो हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेल प्रेमियों व प्रदेशवासियों में इस आयोजन को लेकर उत्साह देखने का मिल रहा है। 26 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न देशों के 186 प्रतिभागियों ने पंजीकरण करवाया है।

उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए नए गंतव्य विकसित किए जा रहे हैं। हाल ही में शिमला ज़िला के जुन्गा में फ्लाइंग फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इससे पहले अप्रैल माह में भी बीड़-बिलिंग में पैराग्लाइडिंग प्री-वर्ल्ड कप आयोजित करवाया गया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं प्रदेश में आयोजित करवाई जाएंगी।

उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया जा रहा है। निगम ने आपदा के दौरान भी अपनी प्रतिबद्धता को जिम्मेदारी से निभाया है और पर्यटकों को सुविधाएं व राहत सामग्री उपलब्ध करवाई गई।

उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रतिभागियों, बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन, पर्यटन विभाग व निगम की पूरी टीम को बधाई दी।

इस अवसर पर शिमला से प्रधान सचिव पर्यटन देवेश कुमार, निदेशक पर्यटन अमित कश्यप तथा निगम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। जबकि बिलिंग पैराग्लाइडिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अनुराग शर्मा सहित अन्य गणमान्य बीड़-बिलिंग में उपस्थित थे।

डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग ने लांच किया डिजिटल इग्निशन कांटेस्ट

शिमला/शैल। प्रदेश के युवाओं में सूचना एवं डिजिटल प्रौद्योगिकी के प्रति रूझान को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस विभाग ने नवोन्मेषी पहल की है। विभाग ने प्रदेश के निजी एवं सरकारी क्षेत्र के छठी कक्षा से लेकर महाविद्यालय स्तर के विद्यार्थियों के लिए राज्य स्तरीय 'डिजिटल-इग्निशन कांटेस्ट' लांच किया है। यह प्रतियोगिता प्रदेश में डिजिटल माध्यम से आयोजित की जाने वाली अपनी तरह की अनूठी पहल है।

सचिव, डिजिटल प्रौद्योगिकी एवं गवर्नेंस डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि मुख्य सचिव, प्रबोध सक्सेना ने यह कांटेस्ट लांच किया। उन्होंने कहा कि युवा सृजनात्मक विचारों से परिपूर्ण होते हैं। इस कांटेस्ट के माध्यम से युवाओं की सृजनशीलता को प्रदेश की उन्नति और विकास में सहभागी बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

डॉ. अभिषेक जैन ने कहा कि प्रौद्योगिकी के विकास से दुनिया भर में अनेक सकारात्मक बदलाव आये हैं। शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग एक विकल्प से कहीं अधिक हो गया है। शिक्षा में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग से विद्यार्थियों की क्षमता और दक्षता को भी बढ़ावा मिला है।

उन्होंने बताया कि यह कांटेस्ट 01 नवम्बर से 10 नवम्बर, 2023 तक आयोजित किया जाएगा। कांटेस्ट में भाग लेने के लिए छठी से आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को समृद्ध हिमाचल प्रदेश के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग' विषय पर एक पीपीटी तैयार करनी होगी। नवमीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को 'शासन, डिजिटल साक्षरता एवं साइबर सुरक्षा के लिए कृत्रिम मेधा (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग' विषय पर प्रश्नोत्तरी सत्र और महाविद्यालय स्तर (12वीं कक्षा से ऊपर) के विद्यार्थियों को 'शासन में कृत्रिम मेधा का उपयोग' विषय पर एक अवधारणा नोट (कांस्पेट नोट) तैयार करना होगा।

उन्होंने बताया कि कांटेस्ट के विजेताओं को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू बाल दिवस के अवसर पर पुरस्कृत करेंगे। हर वर्ग के प्रथम विजेता को पुरस्कार के रूप में एक लाख रुपये, प्रथम उप-विजेता को 60 हजार रुपये और द्वितीय उप-विजेता को 40 हजार रुपये प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से अधिक से अधिक संख्या में इस कांटेस्ट में भाग लेने का आहवान किया।

इस कांटेस्ट में प्रतिभागिता के लिए इच्छुक छात्रों को https://contest.hp.gov.in पर अपनी प्रविष्टि दर्ज करनी होगी। अधिक जानकारी के लिए दूरभाष संख्या 0177-2628914 पर प्रात: 10 बजे से सायं 5 बजे तक किसी भी कार्य दिवस पर सम्पर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने सुन्नी में 174 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जिला शिमला के सुन्नी में तीन दिवसीय जिला स्तरीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने दशहरा के उपलक्ष्य पर आए देवी-देवताओं का आशीर्वाद लिया और प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की।

प्रदेशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं देते हुए ठाकुर सुखविंदर

सिंह सुक्खू ने सुन्नी अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर तक करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल में पर्याप्त चिकित्सकों की नियुक्ति की जाएगी और इसे आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाया जाएगा। उन्होंने भविष्य में सुन्नी में एसडीएम कार्यालय खोलने तथा मिनी सचिवालय के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही मिनी सचिवालय का शिलान्यास भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत शोघी में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने की घोषणा करते हुए कहा कि इसके लिए अगले बजट में प्रावधान किया जाएगा।

इससे पहले, मुख्यमंत्री ने शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लिए 174 करोड़ रुपये की 18 विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने जलोग में 4.69 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन, सुन्नी में 3.71 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित गृह रक्षा भवन और सुन्नी में 88 लाख रुपये की लागत से निर्मित राजकीय कोषागार भवन का लोकार्पण किया।

मुख्यमंत्री ने 5.42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली कढारघाट से पलग सेरीकाडी सड़क, 4.29 करोड़ रुपये की लागत से मंढोड़घाट से जमोग वाया भरगन सड़क, 5.14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली शमलोह-मंढोड़घाट -अणु सड़क, 11.75 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शाननघाटी दाड़गी-सोहल -काटल सड़क, 12.60 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली जलोग-गढेड़ी सड़क, 7.84 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली बघार से जगेहड़ी सड़क, 10.20 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली खेल का चौरा से बागी सड़क, 12.22 करोड़ रुपये से निर्मित होने वाली रूरगा-गवाही-रंगोल सड़क तथा 6.66 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाली शड़ी से सनौला सड़क के की आधारशिला रखी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बसंतपुर में 50.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले बहुतकनीकी संस्थान, 25.16 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली सुन्नी जलापूर्ति योजना के विस्तार कार्य, 2.66 करोड़ रुपये की लागत से कोलडैम से शकरोरी, बसंतपुर, पाहल, न्योट उठाऊ सिंचाई योजना चरण-1 तथा इसी योजना के 4.14 करोड़ रुपये की लागत से चरण-2 के संवर्द्धन कार्य की आधारशिला रखी। उन्होंने 3.72 करोड़ रुपये की लागत निर्मित होने वाली उठाऊ सिंचाई योजना घैनी के विस्तार कार्य तथा 2.04 करोड़ रुपये की लागत से सनौला और नौटी खड्ड के मध्य बनी विभिन्न पुरानी कुहलों के सुधार कार्य की आधारशिला रखी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछली सरकार ने बिजली परियोजनाओं में राज्य के हितों पर ध्यान नहीं दिया, जिसके परिणामस्वरूप कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना 210 मेगावाट की लूहरी चरण-1, 382 मेगावाट की सुन्नी परियोजना तथा 66 मेगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण शुरू हुआ जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटड को नोटिस जारी किए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्नी के लोगों के साथ उनका पुराना रिश्ता है। 40 वर्ष पूर्व वह सुन्नी में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से चर्चा करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्यार्थियों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की।

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने दशहरा के पावन अवसर पर कामना की कि देवी-देवताओं के आशीर्वाद से प्रदेश में शांति और समृद्ध आएगी।

विक्रमादित्य सिंह ने विभिन्न परियोजनाओं के शिलान्यास व उद्घाटन क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने जाखू में किया रावण दहन

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दशहरे के शुभ

अवसर पर श्री हनुमान मंदिर जाखू में पूजा-अर्चना की और प्रदेश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर भी इस अवसर पर उपस्थित थीं।

इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रावण, मेघनाथ और कुंभकरण के पुतलों का दहन भी किया।

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, स्थानीय विधायक हरीश जनारथा, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान, मुख्यमंत्री के ओएसडी रितेश कपरेट, नगर निगम शिमला के पार्षदगण, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी और गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से विराट कोहली ने भेंट की

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू से धर्मशाला में भारतीय क्रिकेट टीम के

दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने भेंट की। इस दौरान दोनों के मध्य क्रिकेट को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने विराट कोहली को न्यूज़ीलैंड के खिलाफ धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में निर्णायक पारी खेलने के लिए बधाई दी। उन्होंने विश्व कप में भारतीय टीम के विजय अभियान जारी रखने पर प्रदेशवासियों की ओर से शुभकामनाएं भी दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय टीम बेहतरीन फॉर्म में है। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया इस बार विश्व कप जीतने की प्रबल दावेदार है। हर भारतीय की भी कामना है कि भारतीय टीम एक बार फिर विश्व कप जीते।

इस अवसर पर हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राजीव शुक्ला, सह प्रभारी तेजिंद्र बिटटू, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा और विधायक सुधीर शर्मा भी उपस्थित थे।

आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एमेच्योर रेडियो को बढ़ावा दे रही प्रदेश सरकार

शिमला/शैल। राज्य में हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा से हर क्षेत्र को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थिति से प्रभावशाली तरीके से निपटने के लिए प्रदेश सरकार संचार के बेहतर वैकल्पिक साधन विकसित करने पर बल दे रही है।

आपदा की स्थिति में जब फोन और इंटरनेट जैसी संचार सेवाएं ठप्प हो जाती हैं तो इससे निपटने के लिए राज्य सरकार ने आपात स्थिति के दौरान वैकल्पिक संचार के लिए एक प्रभावी उपकरण के रूप में एमेच्योर रेडियो (हैम) को बढ़ावा देने को स्वीकृति प्रदान की है।

इस पहल के तहत राज्य के प्रत्येक उप-मण्डल में कम से कम एक हैम रेडियो स्वयंसेवक बनाने की परिकल्पना की गई है। ये स्वयंसेवक किसी भी आपदा या आपातकाल की स्थिति में राज्य स्तर पर स्थापित आपातकालीन संचालन केंद्र और सभी जिला आपातकालीन संचालन केंद्रों से जुड़कर वैकल्पिक संचार चैनल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

इसका प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए, स्वयंसेवकों को पंजीकृत किया जाएगा और स्थापित मानदंडों के अनुसार एमेच्योर रेडियो के संचालन के लिए लाइसेंस भी दिए जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार स्वयंसेवकों को आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। आवश्यक उपकरणों की 80 प्रतिशत लागत का वहन सरकार द्वारा किया जाएगा तथा शेष 20 प्रतिशत लागत स्वयंसेवकों को वहन करनी होगी। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार शैक्षणिक संस्थानों में नए हैम रेडियो क्लब स्थापित करने, मौजूदा हैम रेडियो क्लबों को मजबूत करने और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण प्रदान करने में भी मदद करेगी। प्रशिक्षित एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों के कौशल का उपयोग आवश्यकता और आपात स्थिति के समय सार्वजनिक सेवा के लिए किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि आपातकालीन संचार में एमेच्योर रेडियो का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जब टैलीफोन, मोबाईल फोन सहित अन्य पारम्परिक संचार सेवाएं बाधित हो जाती हैं तो यह रेडियो स्टेशन सूचना सम्प्रेषण में उपयोगी हो सकते हैं। लम्बी दूरी तय कर सकने की इनकी क्षमता के कारण यह आपातकालीन स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं तथा अमूल्य जीवन बचाया जा सकता है। संचार प्रणाली ठप्प होने की स्थिति में इसके माध्यम से आवश्यक सूचनाएं प्रेषित की जा सकती हैं जिससे आपदा के कारण होने वाली क्षति को भी कम किया जा सकता है। आपदा के दौरान स्रोत व्यक्ति, आपातकालीन प्रबंधन से जुड़े लोगों और आपदा प्रभावितों के बीच आपसी सम्पर्क बेहद अहम् होता है।

मुख्यमंत्री का कहना है कि बारिश और सर्दियों के मौसम के दौरान लाहौल-स्पीति, चंबा और किन्नौर जैसे जनजातीय जिलों सहित कई क्षेत्रों में संचार प्रणाली अक्सर ठप्प हो जाती है। ऐसी परिस्थितियों में, संचार के वैकल्पिक साधन के रूप में हैम रेडियो की भूमिका और भी बढ़ जाती है। इसलिए, राज्य सरकार ने भविष्य की चुनौतियों के दृष्टिगत आपातकालीन संचार के एक प्रमुख उपकरण के रूप में हैम रेडियो को बढ़ावा देने का निर्णायक कदम उठाया है।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा द्वारा वर्ष 2023 में एक लाख चालान

शिमला/शैल। हिमाचल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI camera) कैमरा के द्वारा मोटर वाहन नियमों में उल्लंघन के तहत एक लाख चालान वर्तमान वर्ष 2023 में किए गए। हिमाचल प्रदेश पुलिस रोड सेफ्टी के प्रति गंभीर है। हिमाचल प्रदेश में मोटर व्हीकल अधिनियम नियमों को लागू करने के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग कर रही है। हिमाचल प्रदेश में वर्तमान समय में 49 ITMS कैमरा राष्ट्रीय मार्गो एवं राज्य मार्ग में चुनिंदा स्थानों पर लगाए गए हैं। वर्तमान वर्ष में बिना मानव हस्तक्षेप से इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा द्वारा कुल 104268 चालान वाहन अधिनियम के तहत उल्लंघन के किए गए हैं । पिछले एक महीने से ITMS द्वारा किए गए चालानों में वृद्धि हुई है। हिमाचल में यातायात उल्लंघन की जांच के लिए एआई कैमरे बिजली से संचालित हैं, और नियंत्रण कक्ष में डेटा भेजने के लिए 4जी एलटीई तकनीक का उपयोग करेंगे।

प्रारंभ में एआई कैमरे बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चलाना, सीट बेल्ट पहने बिना यात्रा करना, दो पहिया वाहन पर दो से अधिक लोगों का यात्रा करना, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना और लाल बत्ती उल्लंघन जैसे उल्लंघनों का पता लगाएंगे। ''पूर्णत: स्वचालित यातायात प्रवर्तन प्रणाली'' वाहन मालिक को कथित अपराध के 24 घंटों के भीतर ई-मेल और मोबाइल फोन एसएमएस के माध्यम से यातायात उल्लंघन के बारे में सूचित करेगी। ट्रैफिक चालान में फोटोग्राफिक सबूत, उल्लंघन का समय और स्थान होगा। जुर्माना 500 रुपये से लेकर 2,000 रुपये तक है।

एक सिस्टम तीन महीने तक की वीडियो फुटेज संग्रहीत कर सकता है

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

नशे के कैंसर से देश को बचाने का दायित्व किसका?

शिमला/शैल। आज हमारे सामने सबसे बड़ी गम्भीर समस्या नशे की समस्या है। नशे का यह कैंसर जिस तीव्रता से समाज में फैल रहा है उसे देखकर, सुनकर

आदमी सीहर उठता है और लगता है जिस गति से नशा समाज को विनाश की गर्त में ले जा रहा है उससे तो समाज का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जायेगा । प्रतिदिन नशे से होने वाली युवाओं की मौतों की खबरें और नशे की बड़ी बड़ी खेपें पकड़े जाने के समाचार डराते हैं। मानव समाज के अस्तित्व को खतरे में डालने वाला स्वयं मानव समाज ही है। आदमी पैसे के लालच में अन्धा होता जा रहा है। एक समय था जब तम्बाकू, सिगरेट, बीड़ी और अधिक से अधिक शराब को नशा माना जाता था।

आज अफीम, चरस, गांजा, कोकीन, चिट्टा और न जाने कौन कौन से नये नामों के साथ नशा समाज में तवाही मचा रहा है। इस धंधे में जो अन्धाधुंध कमाई हो रही है उसके लालच में लोग इस दलदल में फंसते हैं और जो फंस गये वे फिर निकल नहीं पाते। अधिक से अधिक धन कमाने के लालच में लोग फंसते हैं और वैसे ही बेईमानी का धन कमाने में पुलिस प्रशासन और अन्य एजैंसियां, जिन को इस पर नियन्त्रण करना है, वो भी रिश्वत के चक्कर में आंखें मूंद लेते हैं ।

इसका भयंकर परिणाम यह हो रहा है कि छोटे बच्चे, विद्यार्थी और युवा नशेड़ी बन जाते हैं। परिवार नियोजन के कारण बहुत सारे परिवारों में एक ही बच्चा, लड़का या लड़की होती है और वह मासूम जब नशे की लत का शिकार हो जाते हैं तो मॉ-बाप की जिन्दगी वैसे ही नरक बन जाती है। यदि युवा पीढ़ी नशेड़ होगी तो न सेना के लिये वीर सैनिक मिलेंगे न पुलिस प्रशासन में स्वस्थ जागरूक कर्मचारी, अधिकारी मिल पायेंगे न ही कृषि का क्षेत्र, न उद्योग का क्षेत्र और न ही सेवाओं का क्षेत्र बचेगा। नशे का यह जहर सारे समाज को खोखला करके समाप्त कर देगा ।

ऐसे में प्रश्न उठता है कि करें क्या? इस संकट को दूर करने के लिये कोई बाहर से आकर समाधान नहीं निकालेगा हमें स्वयं प्रत्येक नागरिक को अपना अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाना है। कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि परिवार की परिभाषा पति, पत्नि और बच्चों तक ही सीमित हो गई है। समाज के अन्य लोगों का सुख दुख हमारा अपना नहीं होता। इसी प्रकार से हमारा सुख दुख समाज के लोगों का नहीं होता। इसी कारण से मनुष्य कष्ट या समस्या के समय सामाजिक प्राणी होते हुये भी अपने आप को अकेला पाता है।

कुछ समय पहले तक किसी का भी बच्चा अगर सिगरेट, बीड़ी या शराब आदि का नशा करते किसी को मिलता था तो प्रत्येक व्यक्ति अपना सामाजिक दायित्व समझते हुये उसे रोकता था। उसके परिवारजनों को सूचना देता था तो एक प्रकार से कुरीतियों पर दुष्प्रभावों पर पारिवारिक नियन्त्रण के साथ साथ सामाजिक नियन्त्रण भी होता था । नशे की बात हो, महिलाओं से छेड़खानी की बात हो या कोई दुर्घटना हो जाए तो आंख बचाकर निकलने में ही भलाई समझी जाती है ।

इसलिये पहले तो सभी अपना पारिवारिक दायित्व निभायें केवल बच्चे पैदा करना ही अपना दायित्व न समझें बल्कि उन्हें अच्छे संस्कार देना, बच्चों को समय देना और समाज को सुसंस्कृत, सभ्य नागरिक देना भी सभी का दायित्व है। सामाजिक दायित्व को समझते हुये उसके खिलाफ खड़े होने का नैतिक साहस अपने अन्दर पैदा करें और सामाजिक दायित्व को निभायें, गल्त किसी के साथ भी हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज उठायें।

परिवार और समाज के साथ सरकार पर भी बहुत बड़ा दायित्व आता है इन बुराईयों को कुचलने के लिये सरकार को सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है । इसमें वर्तमान कानूनों में अगर किसी संशोधन की आवश्यकता हो तो केन्द्र और प्रदेश की सरकारें मिलकर सख्त कानून बनायें।

पुलिस प्रशासन के लोग अकसर यह शिकायत करते हैं कि हम तो केस पकड़ते हैं लेकिन अदालत से लोग छूट जाते हैं क्योंकि पकड़ी गई नशे की खेप की मात्रा कम होती है। तो क्या अपराधी इतनी कम मात्रा में लाते हैं या पकड़ने वाले पकड़ी गई खेप की मात्रा कम दिखाते हैं। इसलिये सख्त कानून की आवश्यकता केवल धन के लालच में लगे समाज विरोधी ड्रग तस्करों के लिये नहीं अपितु इसे बनाने वालों, तस्करी करने वालों, नशा फैलाने वालों, प्रयोग करने वालों और पुलिस प्रशासन तथा राजनीतिक संरक्षण देने वालों समेत सब के लिये सख्त कानून की आवश्यकता है। इसके लिये सब को इन सभी समाज विरोधी गतिविधियों में संलिप्त सभी लोगों के विरूद्व सख्त दृष्टिकोण अपनाना होगा और सामान्य कानूनों के तहत मिलने वाले संरक्षण से इन्हें बाहर रखना होगा।

मुझे याद है 1995 में संसद की ''पर्यटन और परिवहन'' की स्थाई समिति के सदस्य के तौर पर सिंगापुर जाने का अवसर मिला। उन दिनों अमेरिका के दो नागरिक नशे की तस्करी के आरोप में सिंगापुर में पकड़े गये थे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने उन्हें छुड़ाने के भरसक प्रयास किये लेकिन प्रधानमन्त्री श्री ली ने एक न सुनी और तीस लाख की आबादी वाले सिंगापुर ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश के नशे के दो तस्करों को अपने देश के कानून के अनुसार फांसी पर लटका दिया।

क्या 140 करोड़ की आबादी वाला नया भारत और यहां के विभिन्न दलों के शासक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर नशे के इस कैंसर से देश को मुक्त करने की इच्छाशक्ति दिखायेंगे और विश्वशक्ति बनने वाला भारत ''नशा मुक्त'' भी होगा? यही हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है और पास कर ली तो सबसे बड़ी उपलब्धि भी होगी ।

प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के पुनः खुलने से पहले ही मुखर हुआ विरोध

कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विनोद कुमार ने लिखा पत्र

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार प्रशासनिक ट्रिब्यूनल फिर से खोलने का प्रयास कर रही है। यह ट्रिब्यूनल भारत सरकार की अनुमति से ही खुल सकता है और केंद्र सरकार की अनुमति के लिए इस आश्य का प्रस्ताव भेजा जा चुका है। लेकिन यह ट्रिब्यूनल दोबारा खोलने की चर्चा जैसे ही सामने आई उसी के साथ इसके विरोध के स्वर भी मुखर होने लग गये हैं। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद कुमार और उनके साथियों ने इसके विरोध का मोर्चा खोल दिया है। इन कर्मचारी नेताओं का मानना है कि कर्मचारियों के मामले में न्याय के लिये प्रदेश उच्च न्यायालय से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इनका कहना है पहले भी यह ट्रिब्यूनल कर्मचारियों के प्रस्ताव पर ही बंद किया गया था। उन्होंने तर्क दिया है कि पंजाब और हरियाणा में कर्मचारियों और उनके मामलों की संख्या दो गुणी है परन्तु वहां पर तो कोई ट्रिब्यूनल नहीं है और उच्च न्यायालय के माध्यम से ही त्वरित न्याय मिल रहा है। कर्मचारी नेताओं का आरोप है कि हिमाचल में यह ट्रिब्यूनल कुछ सेवानिवृत नौकरशाहों और अन्यों की शरण स्थली से अधिक कुछ साबित नहीं हुआ। विनोद कुमार ने खुलासा किया है कि पूर्व में भी जब यह ट्रिब्यूनल बन्द करने की मांग की गई थी तब भी दो नौकरशाह श्रीकांत बाल्दी और मनीषा नन्दा कि इसमें नियुक्तियां फाइनल हो गई थी तब ट्रिब्यूनल को भंग करने की मांग न करने के लिए उन्हें कहा गया था। लेकिन कर्मचारी हित में वह मांग पर कायम रहे और परिणाम स्वरूप ट्रिब्यूनल भंग हो गया। विनोद कुमार ने जोर देकर कहा कि इस फैसले का विरोध करने के लिए वह राज्यपाल से लेकर केंद्र सरकार तक भी अपना पक्ष रखेंगे। उन्होंने सुक्खू सरकार को सलाह दी है कि वित्तीय संकट से जूझ रहे प्रदेश पर 100 करोड़ का अतिरिक्त बोझ कुछ नौकरशाहों के लिए न डाला जाये।